Further, with the upgradation and encadrement of posts in the higher grades and stoppage of lateral entry at Grade I and Grade II levels (now merged to Junior Administrative Grade) in recent years, there has been improvemnt in promotional avenues. Promotions were made on regular basis to fill one vadancy in the Higher Administrative Grade and six in the Senior Administrative Grade. Promotions were also made on ad-hoc basis to fill up vacancies in the Junior Administrative Grade and Grade III, pursuant to permission of the Supreme Court in the then pending Civil Appeal. Steps for promotion on regular basis to Grade III and JAG and under way subsequent to the final orders of the Supreme Court in April, 1992.

गुजरात में विकास कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय सहायता

*365. **श्री राज भाई ए० परमार : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या केंद्रीय सरकार गुजरात से संबंधित स्कीमों/कार्यक्रमों/विकास परियोजनाओं और क्रियाकलापों के लिए सहायता देती है ; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान गुजरात में प्रत्येक विकास योजना के लिए कितनी-कितनी सहायता राशि दी गई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) सरकार गुजरात सहित सभी राज्यों को ब्लाक ऋणों और अनुदान के रूप में केन्द्रीत सहायता प्रदान करती है ।

(ख) गुजरात को फार्मूला आधारित (नेट) केंद्रीय सहायता के रूप में वर्ष 1990-91, 1991-92 में क्रमश: 171.74 करोड़ रुपए और 199.01 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे ।

Additional fruit processing by M/s. Pepsi Foods Limited

*368. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether M/s. Pepsi Foods Limited, has any plan to process additional quantities of fruits during this year;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) what is the amount of investment made by the company so far, in infrastructural and human resource for the Crop Development Programme in Punjab;

(d) whether the income accruing to the farmers in Punjab has been increasing due to the crop development programme of the company; and

(e) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) Yes, Sir.

(b) M/s. Pepsi Foods Limited has plans of processing 43,000 tons of Fruits/vegetables during 1992-93.

(c) The Company does not maintain separate record for investment in crop development. However, its fruit processing Division in Punjab had a total investment of Rs. 20 crores in fixed assets as on 31.3.1991.

(d) Yes, Sir.

(e) M/s. Pepsi Foods Limited has estimated that farmer revenue from Tomato alone in the State of Punjab have gone up from Rs. 150 lakhs in

1989 to Rs. 843 lakhs in 1992. These are based on average yield, average selling prices and estimated total acreage for the crop.

Assistance from FAO

*369. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to refer to answer to Unstarred Question 398 given in the Rajya Sabha on the 13th July, 1992 and state:

(a) whether FAO has offered any financial assistance for implementing its recommendations on the sustainability of deep sea fishing in India;

(b) if so, whether any funds have been earmarked for Andhra Pradesh; and

(c) whether Government propose to implement the recommendations of F.A.O. made in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Yes, Sir.

आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान एक कोष स्थापित किया जाना

*370. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
डा. जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में कपड़ा मिलों में हो रहे निरंतर घाटे को दूर करने और उनका आधुनिकीकरण करने तथा कपड़ा उद्योग में निर्यात को बढ़ाने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान एक कोष स्थापित करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कोष में कुल कितनी राशि रखी जाएगी ;

(ग) क्या सरकार ने इस समय रुग्ण सभी कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक राशि का अनुमान लगाया है ; और

(घ) यदि हां, तो यह अनुमानित राशि कितनी है और क्या इस कोष में से राशि व्यय करने के लिए प्राथमिकतायें निर्धारित की गई हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) वर्ष 1985 की वस्त्र नीति के अनुसरण में आई०डी०सी०आई० ने वस्त्र मिलों की आधुनिकीकरण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 750 करोड़ रु० की राशि का निर्धारण कर वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना का सृजन किया था । वस्त्र मंत्रालय ने आठवीं योजना अवधि के दौरान इस योजना को जारी रखने का प्रस्ताव किया है । वस्त्र मिलों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है तथा वस्त्र मिलों सहित औद्योगिक एकक को प्रदान की जाने वाली आधुनिकीकरण सहायता की मात्रा उसकी आवश्यकता तथा संस्थानों की अर्थसमता/वित्तीय मानदण्डों को पूरा करने के सामर्थ्य पर निर्भर करती है । अतः आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक अपेक्षित राशि का निर्धारण करना संभव नहीं है ।

Joint venture units

*371. DR. ABRAR AHMED:
SHRI SURESH KALMADI:

Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state: